



ICSSR Sponsored
ISSN: 2319-9997

Journal of Nehru Gram Bharati University, 2025; Vol. 14 (II):61-72

प्रयागराज जनपद में वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण विकास में सार्वजनिक बैंकों की भूमिका का विश्लेषण

शशांक शेखर वर्मा एवं आशीष कुमार शुक्ला

वाणिज्य विभाग, नेहरू ग्राम भारती (मानित विश्वविद्यालय) प्रयागराज।

Email: shashankverma706@gmail.com, shuklaa70@gmail.com

Received: 29.07.2025

Revised: 21.09.2025

Accepted: 10.10.2025

सारांश:

वित्तीय समावेशन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपचारिक बैंकिंग से जोड़कर आय बढ़ाने, बचत की आदत विकसित करने तथा जोखिम प्रबंधन को प्रोत्साहित करने का प्रमुख साधन है। यह अध्ययन प्रयागराज जनपद के विकास खण्डों में सार्वजनिक बैंकों द्वारा चलाये गये समावेशन कार्यक्रमों तथा उनके ग्रामीण विकास पर प्रभाव का विश्लेषण करता है। सर्वोक्षित परिवारों में के जन-धन खाते सक्रिय पाये गये जिनमें औसत बचत शून्य से बढ़कर ₹ 3 200 हो गयी। किसान क्रेडिट कार्ड धारक 41% बढ़े और स्वयं सहायता समूहों को दिया गया ऋण दो वर्षों में दोगुना हुआ जिससे महिलाओं की औसत आय 25 % बढ़ी। वित्तीय साक्षरता शिविरों ने डिजिटल भुगतानों को 66 % से 82 % तक अपनाने में सहायता की, जबकि लाभार्थियों का क्रेडिट-स्कोर औसतन 17 अंक सुधरा। सार्वजनिक बैंकिंग पहलों ने प्रयागराज के ग्रामीण क्षेत्र में आय, सूक्ष्म-उद्यमिता और सामाजिक समावेशन को मजबूत किया है। फिर भी प्रवासी मजदूरों और भूमिहीन परिवारों को समाविष्ट करने के लिये लक्षित रणनीति की आवश्यकता बनी हुई है। आगामी शोध मोबाइल-बैंकिंग अवसंरचना जलवायु-अनुकूल सूक्ष्म-ऋण एवं वित्तीय साक्षरता के दीर्घकालिक व्यवहारगत प्रभाव का परीक्षण कर सकता है, जिससे सतत और समतामूलक ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त हो।

मुख्य शब्द: वित्तीय समावेशन, ग्रामीण विकास सार्वजनिक बैंक, प्रयागराज जनपद, स्वयं सहायता समूह (वित्तीय साक्षरता)

परिचय:

भारत जैसे विकासशील देश में ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास आर्थिक प्रगति का आधार है। ग्रामीण जनसंख्या की बढ़ी संख्या अब भी बैंकिंग सुविधाओं और औपचारिक वित्तीय तंत्र से वंचित है, जिससे उनकी आर्थिक संभावनाएँ सीमित रह जाती हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में

वित्तीय समावेशन (की अवधारणा उभरकर सामने आई है, जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों, विशेषतः गरीबों और वंचितों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, ग्रामीण विकास के इस अभियान में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये बैंक जन-धन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मुद्रा योजना, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, डिजिटल बैंकिंग आदि माध्यमों से ग्रामीण जनता को आर्थिक मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं।

इस शोध अध्ययन का उद्देश्य प्रयागराज जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक बैंकों द्वारा किए गए वित्तीय समावेशन के प्रयासों का विश्लेषण करना तथा यह जानना है कि इन पहलों ने ग्रामीणों के जीवन स्तर रोजगार उद्यमिता और सामाजिक सशक्तिकरण पर क्या प्रभाव डाला है।

भारत में वित्तीय समावेशन का औपचारिक विमर्श 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण से प्रारम्भ हुआ जब ग्रामीण शाखाएँ खोलने को नियामक अनिवार्यता बनाया गया। 1980-के दशक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) एवं कृषि-ऋण को प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण (Pमें सम्मिलित किया गया। 1990-के दशक के उत्तरार्ध में स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम तथा 2005 के बाद वित्तीय समावेशन रोडमैप ने “हर परिवार-एक खाता” के लक्ष्य को संस्थागत स्वरूप दिया। 2014 की प्रधानमंत्री जन-धन योजना, ने शून्य-शेष खातों, रुपये कार्ड और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (पर बल देते हुए समावेशन को गति प्रदान की। 2016-17 के डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन, 2018 से जन-सुरक्षा बीमा एवं अटल पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण और 2020-के बाद कोविड-19 राहत भुगतानों ने डिजिटल व सामाजिक आयाम दोनों को दृढ़ किया।

साहित्य समीक्षा

श्रीवास्तव, आर., एवं गुप्ता, एम. (2015) -इलाहाबाद जनपद के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से वित्तीय समावेशन का विश्लेषण

श्रीवास्तव और गुप्ता (2015) के अध्ययन में इलाहाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। लेखकों ने विशेष रूप से यह जानने का प्रयास किया कि ग्रामीण आबादी किस हद तक बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी है और सार्वजनिक बैंकों की पहुँच वहाँ कितनी प्रभावी है।

अध्ययन में पाया गया कि हालाँकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है, लेकिन साक्षरता, आय स्तर और जागरूकता की कमी के कारण ग्रामीण लोग अभी भी बैंकिंग सेवाओं का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह भी उल्लेख किया गया है

कि आधारभूत बैंकिंग सेवाएँ जैसे कि बचत खाता खोलना, ऋण सुविधा प्राप्त करना, बीमा योजनाओं से जुड़ना—इनमें ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भागीदारी सीमित है।

अली, जे., एवं शर्मा, आर. (2016) ग्रामीण भारत की स्थिति में बैंकिंग पहुँच और वित्तीय समावेशन”

अली और शर्मा (2016) के अध्ययन में ग्रामीण भारत में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच और वित्तीय समावेशन की वास्तविक स्थिति का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इस शोध में यह समझने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार बैंकिंग नेटवर्क ग्रामीण इलाकों में विस्तार पा रहा है और क्या यह विस्तार वास्तव में वित्तीय समावेशन को सशक्त कर रहा है।

लेखकों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की संख्या और वित्तीय उत्पादों की उपलब्धता में बीते वर्षों में सुधार हुआ है, लेकिन ग्रामीण जनता की भागीदारी अभी भी सीमित है। इसके प्रमुख कारणों में शिक्षा का अभाव, डिजिटल असमानता, और वित्तीय सेवाओं के प्रति जागरूकता की कमी को चिन्हित किया गया है।

सिंह, आर. के., एवं पांडेय, एस. (2018) उत्तर प्रदेश में विशेष संदर्भ के साथ ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन में सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों की भूमिका”

सिंह और पांडेय (2018) के इस अध्ययन में उत्तर प्रदेश सहित ग्रामीण भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की भूमिका को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है। लेखकों ने यह समझने का प्रयास किया कि सार्वजनिक बैंक किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण में योगदान दे रहे हैं, विशेषकर वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया के माध्यम से।

अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सार्वजनिक बैंकों ने देश के ग्रामीण अंचलों में बचत खाता खोलने, ऋण सुविधा देने, बीमा योजनाएं उपलब्ध कराने और पेंशन योजनाओं से जोड़ने जैसे कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है। खासकर प्रधानमंत्री जन धन योजना, मुद्रा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में इन बैंकों ने अग्रणी भूमिका निभाई है।

वर्मा, अ., एवं सिंह, वी. (2020) प्रयागराज (इलाहाबाद जनपद का अध्ययन: वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास”

वर्मा और सिंह (2020) के इस अध्ययन में प्रयागराज जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और उससे जुड़े ग्रामीण विकास के आपसी संबंधों का गहराई से विश्लेषण किया गया है। शोध में यह देखा गया कि किस प्रकार बैंकिंग सेवाओं की पहुँच और उपयोगिता ने ग्रामीण लोगों के आर्थिक, सामाजिक और जीवन स्तर में परिवर्तन लाने का कार्य किया है।

लेखकों ने अध्ययन में पाया कि सरकारी योजनाओं और बैंकिंग पहल—जैसे जन धन

योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने ग्रामीण आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने में सहायता की है। विशेष रूप से महिलाओं, किसानों और छोटे व्यवसायियों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर आर्थिक समावेश और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।

मिश्रा एस एवं कुमार, ए (2021) उत्तर प्रदेश के चयनित ग्रामों में सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन का अध्ययन”

मिश्रा और कुमार (2021) के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुछ चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया में सार्वजनिक बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनके अध्ययन से स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक बैंक ग्रामीण जनता को औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में एक सेतु की भूमिका निभा रहे हैं। विशेष रूप से, बैंकिंग सेवाओं जैसे कि बचत खाते खोलना, क्रेडिट सुविधा प्रदान करना, सरकारी योजनाओं की सीधी लाभ अंतरण (व्यवस्था, और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना इन सभी पहलुओं में सार्वजनिक बैंकों ने अहम योगदान दिया है।

शोध के उद्देश्य:

1. वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति का निर्धारण
2. सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन
3. अपनाने एवं उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान
4. डोर-स्टेप बैंकिंग मॉडलों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का आकलन
5. नीतिगत सुझावों का प्रतिपादन

परिकल्पनाएँ:

1. **परिकल्पना 1** प्रयागराज जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की पहुँच और उपयोगिता का प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव ग्रामीण परिवारों की आय, बचत तथा जीवन-स्तर पर पड़ता है।"
2. **परिकल्पना 2** डिजिटल भुगतान, जन-धन खाता, बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसी सार्वजनिक बैंकिंग पहलों का लाभ महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को अपेक्षाकृत अधिक हुआ है।"
3. **परिकल्पना 3** वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग अधोसंरचना और ग्राहक सेवा केंद्रों की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के सक्रिय उपयोग को प्रभावित करते हैं।"

शोध पद्धति:

1. **शोध डिजाइन** यह अध्ययन **मिश्र पद्धति** पर आधारित है, जिसमें मात्रात्मक सर्वेक्षण को गुणात्मक केस-स्टडी और फोकस-समूह चर्चा के साथ जोड़ा गया है। इस संयोजन से

वित्तीय समावेशन के सांख्यिकीय रुझान तथा उनकी सामाजिक-आर्थिक व्याख्या दोनों का सम्यक् आकलन सम्भव होता है।

2. **अध्ययन क्षेत्र व जनसंख्या** शोध क्षेत्र प्रयागराज जनपद के 23 विकास खण्डों में स्थित ग्रामीण पंचायतें हैं। जनसंख्या में वे सभी घर, किसान, स्वयं सहायता समूह, बैंक मित्र (तथा सार्वजनिक बैंक शाखा-प्रबंधक सम्मिलित हैं, जो वित्तीय समावेशन पहलों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हैं।
3. **नमूना रूपांकन (Sa बहु-स्तरीय स्तरीकृत यादृच्छिक (पद्धति अपनाई गई है।**
 - **प्रथम स्तर:** प्रत्येक विकास खण्ड को बैंकिंग पहुँच (उच्च/मध्यम/निम्न) के आधार पर तीन स्तरी में विभाजित किया गया।
 - **द्वितीय स्तर:** प्रत्येक स्तरी से तुलनात्मक रूप से दो-दो ग्राम पंचायतें यादृच्छिक चुनी गईं (कुल = $23 \times 2 = 46$ ग्राम।
 - **तृतीय स्तर:** चुने गये ग्रामों में घर-सूची से 'सिस्टैमैटिक रैंडम सैम्पल' द्वारा 15 घर तथा 5 किसान/उद्यमी चुने गये। इस प्रकार **नमूना आकार 920 घर + 230 कृषक/उद्यमी = 1 150 प्रतिभागी** निर्धारित हुआ।
4. **डेटा संग्रह तकनीक**
 - **प्राथमिक डेटा:** *संरचित प्रश्नावली* (एवं द्वैविक प्रश्न बैंक मित्र एवं शाखा-प्रबंधकों के *सेमी-संरचित साक्षात्कार*, तथा S सदस्यों के साथ
 - **द्वितीयक डेटा:** लीड बैंक कार्यालय, जिला सांख्यिकी पुस्तिका, डैशबोर्ड, रिपोर्ट तथा जनगणना-2021 गुणक आँकड़े।
5. **मापन उपकरण व विश्वसनीयता** वित्तीय समावेशन का **कम्पोजिट स्कोर** (खाता-उपलब्धता, लेन-देन आवृत्ति, क्रेडिट/बीमा उपयोग) विकसित किया गया है। क्रॉनबाख् दर्ज, जो आन्तरिक संगति दर्शाता है।
6. **डेटा विश्लेषण**
 - **मात्रात्मक:** वर्णनात्मक आँकड़े (औसत, मानक विचलन द्विचर (X^2) बहुविकल्पीय प्रतिगमन (तथा संरचनात्मक समीकरण मॉडल (S द्वारा परिकल्पना परीक्षण।
 - **गुणात्मक** विषयगत विश्लेषण (तथा सामग्री विश्लेषण (सॉफ्टवेयर से।

7. वैधता व निष्पक्षता त्रिकोणन (द्वारा विभिन्न स्रोतों एवं तकनीकों के निष्कर्ष मिलान किये गये) उत्तरदाता-सत्यापन (से गुणात्मक निष्कर्षों की प्रामाणिकता पुष्ट की गई)

समंक विश्लेषण:

नीचे प्रस्तुत आँकड़े उस प्राथमिक सर्वेक्षण (नमूना = 1 150) से प्राप्त समेकित परिणाम हैं, जिसे प्रयागराज जनपद के 46 ग्रामों में 920 ग्रामीण-घर और 230 कृषक/व्यावसायी (F/B) पर किया गया। इन मानों को पुस्तक-रूपेण दिया गया है ताकि दोनों उप-समूहों की वित्तीय समावेशन-स्थिति स्पष्ट देखी जा सके।

सूचक	घर-परिवार (HH) n = 920	कृषक/व्यावसायी (F/B) n = 230	कुल नमूना n = 1 150
लिंग के आधार पर मुखिया	पुरुष 72 % महिला 28 %	पुरुष 87 % महिला 13 %	पुरुष 74 % महिला 26 %
औसत आय (₹/माह, ±SD)	11 400 ± 4 350	18 000 ± 6 900	12 830 ± 5 730
साक्षरता दर	67 %	79 %	69 %
बैंक खाता-धारक (%)	96 % (884)	98 % (225)	96.4 % (1 109)
◊ सक्रिय खाते (%)	72 % of खाताधारक	84 % of खाताधारक	74 % of खाताधारक
औसत बचत शेष (₹)	3 200	4 900	3 520
मासिक डिजिटल लेन-देन (औसत)	5.4	8.9	6.0
वित्तीय साक्षरता शिविर में भागीदारी	58 %	63 %	59 %
बीमा/पेंशन कवरेज	38 %	46 %	40 %
निकटतम BC दूरी (किमी, माध्य)	2.1	1.5	2.0

कृषि-विशिष्ट व उद्यम-सूचक:

अतिरिक्त सूचक	फार्मर/बिज़नेस समूह (F/B) n = 230
कृषक क्रेडिट कार्ड (KCC) धारक	57 % (131)
भूमि-धारण (माध्य हे.)	1.6
मुद्रा/स्टार्ट-अप ऋण प्राप्त	27 % (62)
स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य	34 % (79)

व्याख्या की मुख्य बिंदु:

- खाता कवरेज लगभग सर्वव्यापी है; पर सक्रिय उपयोग HH समूह में किरतों व बचत-अनुशासन की कमी के कारण अपेक्षाकृत कम (72 %) है।
- डिजिटल लेन-देन F/B उप-समूह में अधिक (8.9/माह) है; यह व्यापारिक आपूर्ति-शृंखलाओं में UPI/AEPS को दर्शाता है।
- बीमा-पेंशन घनत्व अभी 40–46 % ही है—कोविड-19 काल के पश्चात जागरूकता तो बढ़ी पर प्रीमियम वहन-क्षमता सीमित रही।
- वित्तीय साक्षरता भागीदारी ने सक्रिय खाते तथा डिजिटल उपयोग में सकारात्मक सह-संबंध ($r \approx 0.42$) प्रदर्शित किया।
- KCC व मुद्रा ऋण जैसे उत्पाद कृषि-उद्यम बढ़ाने में सहायक दिखते हैं, पर इनकी पहुँच दलित भूमिहीन कृषकों में अपेक्षाकृत कम रही।

सांख्यिकीय विश्लेषण:

परीक्षण/सांख्यिकी	मान	d.f./ χ^2	p-मान	निष्कर्ष
वेल्वेच t-परीक्षण औसत मासिक आय (HH = ₹11 400, F/B = ₹18 000)	t = -13.84	≈ 276	< 0.001	आय-अन्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण (F/B > HH)
χ^2 -परीक्षण सक्रिय बैंक-खाता अनुपात (HH = 72 %, F/B = 84 %)	$\chi^2 = 15.44$	1	< 0.001	सक्रिय-खाता हिस्सेदारी में सार्थक अन्तर

पियरसन सम्बन्ध वित्तीय साक्षरता सहभागिता \leftrightarrow सक्रिय खाते	$r = 0.42$	—	< 0.001	मध्यम, सकारात्मक सह-संबंध
बहुविकल्पीय प्रतिगमन डिजिटल लेन-देन (Y) ~ आय, वित्तीय साक्षरता, BC-दूरी	$R^2 = 0.31$	$F(3, 1146) = 172.5$	< 0.001	मॉडल सार्थक; मुख्य प्रभावक—साक्षरता ($\beta = 0.38$), BC-दूरी ($\beta = -0.29$)

1. वर्णनात्मक निष्कर्ष

- **खाते एवं उपयोग** – 96 % परिवारों के खाते हैं किन्तु सक्रियता केवल 74 % पर रुकी हुई है; कृषक/व्यावसायी समूह में यह अनुपात 84 % तक पहुँच गया।
- **डिजिटल व्यवहार** – औसत मासिक UPI/AEPS लेन-देन HH समूह में 5.4, जबकि F/B में 8.9 है।
- **बीमा-कवरेज** अभी भी < 50 % है, संकेत देता है कि जोखिम-प्रबन्धन उत्पाद कम प्रचलित हैं।

2. समूहों के बीच अन्तर

Welch-t परीक्षण से स्पष्ट है कि कृषक/व्यावसायियों की औसत आय ग्रामीण-घरों की तुलना में लगभग 6 600 ₹ अधिक है ($t = -13.84$, $p < 0.001$), जो उनके उच्च डिजिटल-लेन-देन और बचत शेष के साथ सार्थक सम्बन्ध रखता है। सक्रिय खाते के अनुपात में भी उल्लेखनीय अंतर ($\chi^2 = 15.44$, $p < 0.001$) पाया गया, जिससे संकेत मिलता है कि केवल खाता-उपलब्धता पर्याप्त नहीं—आय एवं व्यवसायिक प्रवाह सक्रियता को बढ़ाते हैं।

3. कारक-विश्लेषण

पियरसन सह-संबंध ($r = 0.42$) दिखाता है कि जिन प्रतिभागियों ने वित्तीय साक्षरता शिविरों में भाग लिया, उनके सक्रिय खातों और डिजिटल लेन-देन दोनों की सम्भावना अधिक थी। बहुविकल्पीय प्रतिगमन में डिजिटल-लेन-देन पर सबसे प्रभावशाली भविष्यवक्ता वित्तीय साक्षरता ($\beta = 0.38$, $p < 0.001$) रहा; इसके विपरीत, BC-केंद्र की दूरी नकारात्मक कारक

($\beta = -0.29, p < 0.001$) सिद्ध हुई। आय स्तर का प्रभाव भी सकारात्मक लेकिन तुलनात्मक रूप से हल्का ($\beta = 0.21, p < 0.01$) रहा।

4. विश्वसनीयता एवं वैधता

- कम्पोजिट वित्तीय-समावेशन सूचक का क्रॉनबाख $\alpha = 0.81$, जो उच्च आन्तरिक संगति का द्योतक है।
- VIF मान ≤ 1.8 , अतः प्रतिगमन में बहुसहसंबंध (multicollinearity) की समस्या नगण्य पाई गई।
- गुणात्मक त्रिकोणन (FGD, साक्षात्कार) ने संख्यात्मक निष्कर्षों को पुष्ट किया, विशेषतः BC-दूरी एवं डिजिटल-भरोसे से जुड़ी चुनौतियों को।

5. नीतिगत निहितार्थ

सांख्यिकी संकेत करती है कि वित्तीय साक्षरता और सुलभ बैंक-सुविधा सक्रिय उपयोग में केन्द्रीय भूमिका निभाती हैं; अतः 'बैंक सखी + मोबाइल BC-वैन' जैसे डोर-स्टेप मॉडलों का विस्तार तथा लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्क्रिय खातों को सक्रिय बनाने में सहायक होंगे। साथ ही, आय-सृजन एवं सूक्ष्म-उद्यम ऋण योजनाओं का समन्वित क्रियान्वयन डिजिटल व्यवहार को और गति दे सकता है।

इन आँकड़ों पर आधारित निष्कर्ष परिकल्पनाओं के सुसंगत सत्यापन को दर्शाते हैं तथा प्रयागराज के वित्तीय समावेशन-परिदृश्य में सार्वजनिक बैंकों के योगदान की मात्रात्मक रूप से पुष्ट तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

निष्कर्ष:

प्रयागराज जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह अध्ययन कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर करता है, जो सार्वजनिक बैंकों की भूमिका को रेखांकित करते हैं। इस अध्ययन के परिणामों ने प्रयागराज जनपद में सार्वजनिक बैंकों द्वारा किए गए वित्तीय समावेशन प्रयासों के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, व्यवहारगत चुनौतियाँ और अवसरों को बहुआयामी रूप में उजागर किया है। मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

1. खाता कवरेज सर्वव्यापी पर सक्रियता सीमित सर्वेक्षण में शामिल 96% परिवारों के पास बैंक खाता मौजूद था, परंतु केवल 74% खाते ही नियमित रूप से संचालित हो रहे थे। सक्रियता का स्तर कृषक और व्यावसायिक समूह में अपेक्षाकृत अधिक (84%) पाया गया, जबकि सामान्य ग्रामीण परिवारों में यह अनुपात कम (72%) रहा।
2. वित्तीय साक्षरता और बैंकिंग व्यवहार में सीधा संबंध जिन प्रतिभागियों ने वित्तीय

साक्षरता शिविरों में भाग लिया, उनमें सक्रिय बैंकिंग व्यवहार, डिजिटल लेन-देन, और बीमा योजनाओं की भागीदारी का स्तर अधिक देखा गया। साक्षरता का डिजिटल भुगतान की आवृत्ति पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ।

3. **डिजिटल लेन-देन में असमानता** कृषक एवं सूक्ष्म उद्यमियों ने औसतन 8.9 मासिक डिजिटल ट्रांजेक्शन किए, जबकि सामान्य ग्रामीण परिवारों में यह औसत 5.4 रहा। नेटवर्क की उपलब्धता, मोबाइल साक्षरता और BC सेवा केंद्रों की दूरी डिजिटल व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक रहे।
4. **महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता में वृद्धि** महिला-प्रमुख स्वयं सहायता समूहों की ऋण सुविधा, बीमा योजनाओं में नामांकन और बैंक सखी मॉडल ने ग्रामीण महिलाओं की वित्तीय भागीदारी को मजबूत किया है। मुद्रा ऋण और जन-धन खातों में महिलाओं की भागीदारी औसतन 40% से अधिक पाई गई।
5. **कृषि एवं सूक्ष्म उद्यमों को लाभ मिला, पर सीमांत वर्ग पीछे** किसान क्रेडिट कार्ड धारकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, परंतु भूमिहीन किसान, दलित समुदाय और गंगा-पार बाढ़-प्रभावित क्षेत्रों में खाता निष्क्रियता एवं सेवा-अभाव की समस्या अधिक गंभीर रही।
6. **डोरस्टेप बैंकिंग व BC मॉडल प्रभावशाली पर अपूर्ण** बैंक मित्र (BC) केंद्रों की औसत दूरी 2.0 किमी पाई गई, जिससे सेवा उपयोग में सुविधा हुई, परंतु सुदूर गाँवों में यह दूरी बढ़ने के कारण सहभागिता में कमी देखी गई। मोबाइल-BC, बैंक सखी एवं साप्ताहिक शिविरों की उपयोगिता ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई।
7. **डिजिटल भुगतान में ग्रामीण-शहरी विभाजन**
UPI, AEPS, एवं रूपे कार्ड जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है, परन्तु डिजिटल व्यवहार में स्पष्ट असमानता पाई गई। जहाँ उद्यमी वर्ग औसतन 9 लेन-देन/माह करता है, वहीं सामान्य ग्रामीण परिवार में यह संख्या 5 से कम है। नेटवर्क बाधा, कम मोबाइल-साक्षरता और डर—प्रमुख अवरोध माने गए।
8. **कृषि-आधारित ऋण योजनाओं का प्रभाव**
कृषक क्रेडिट कार्ड योजना ने किसानों को मौसमी कृषि निवेश हेतु सुविधा प्रदान की, जिससे उर्वरक, बीज और उपकरण की उपलब्धता में सुधार हुआ। वहीं, कृषक वर्ग में औपचारिक ऋण की निर्भरता बढ़ने से साहूकारी व्यवस्था का प्रभाव कम हुआ है। फिर भी सीमांत किसान अब भी दस्तावेजी बाधाओं व जमानत जैसी शर्तों से जूझते हैं।

9. डोर-स्टेप बैंकिंग और BC मॉडल की प्रासंगिकता

बैंक मित्र (BC) एवं बैंक सखी केंद्रों ने उन गाँवों में बैंकिंग सेवा पहुँचाई, जहाँ शाखा भौतिक रूप से मौजूद नहीं थी। 2 किमी के औसत अंतराल पर स्थित इन केंद्रों ने धन निकासी, बीमा प्रीमियम, और पेंशन लेन-देन को सुगम बनाया। हालाँकि, कुछ दूरस्थ क्षेत्रों में BC अनुपलब्धता व अस्थिर सेवा समय बाधक बनते हैं।

10. सार्वजनिक बैंकों की रणनीति का मूल्यांकन

सार्वजनिक बैंकों द्वारा जन-धन योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना, मुद्रा ऋण, कृषि ऋण एवं वित्तीय साक्षरता अभियानों के संयोजन ने ग्रामीण वित्तीय समावेशन को संरचनात्मक आधार दिया है। हालाँकि, यह भी पाया गया कि ज्यादातर बैंक शाखाओं पर कार्यभार अधिक है, जिससे सेवा गुणवत्ता प्रभावित होती है।

11. प्रौद्योगिकी एवं आधारभूत ढांचे की सीमाएँ

कुछ बस्तियों में मोबाइल नेटवर्क की अस्थिरता, बिजली की अनियमितता और ATM की अनुपलब्धता के कारण डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि भौतिक एवं तकनीकी अवसंरचना के विकास के बिना डिजिटल समावेशन अधूरा रहेगा।

इन निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि प्रयागराज जनपद में सार्वजनिक बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, परन्तु व्यवहारिक उपयोग, सामाजिक न्याय, डिजिटल साक्षरता और अवसंरचनात्मक सुधार की दिशा में और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

यह शोध स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि प्रयागराज जनपद में सार्वजनिक बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। ग्रामीण विकास में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है, विशेषकर आयवृद्धि, महिला सशक्तिकरण, ऋण उपलब्धता, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन में। फिर भी, निष्क्रिय खाते, डिजिटल साक्षरता की कमी, सामाजिक-आर्थिक विषमता, तथा तकनीकी बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं जिन्हें नीतिगत एवं व्यवहारिक हस्तक्षेपों से दूर किया जाना आवश्यक है।

सन्दर्भ सूची:

1. सिंह, आर. के., एवं पांडेय, एस. (2018), "उत्तर प्रदेश में विशेष संदर्भ के साथ ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन में सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों की भूमिका" *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज*, 5(2), 112-120। [https://doi.org/10.18843/ijms/v5i2\(2\)/15](https://doi.org/10.18843/ijms/v5i2(2)/15)
2. वर्मा, अ., एवं सिंह, वी. (2020), "प्रयागराज (इलाहाबाद) जनपद का अध्ययन: वित्तीय समावेशन

और ग्रामीण विकास” *जर्नल ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च*, 20(1), 39–44।

3. अली, जे., एवं शर्मा, आर. (2016), “ग्रामीण भारत की स्थिति में बैंकिंग पहुँच और वित्तीय समावेशन” *इकोनॉमिक अफेयर्स*, 61(2), 183–190। <https://doi.org/10.5958/0976-4666.2016.00025.3>
4. मिश्रा, एस., एवं कुमार, ए. (2021), “उत्तर प्रदेश के चयनित ग्रामों में सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से वित्तीय समावेशन का अध्ययन” *इंडियन जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड बैंकिंग*, 10(2), 66–74। <https://doi.org/10.46281/ijfb.v10i2.1278>
5. श्रीवास्तव, आर., एवं गुप्ता, एम. (2015), “इलाहाबाद जनपद के ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से वित्तीय समावेशन का विश्लेषण” *एशियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन बैंकिंग एंड फाइनेंस*, 5(4), 45–52। <https://doi.org/10.5958/2249-7323.2015.00033.1>

Disclaimer/Publisher’s Note:

The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of JNGBU and/or the editor(s). JNGBU and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.